भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3655
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शैक्षिक अवसंरचना का अभाव

3655. **श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों के अनेक सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और डिजिटल शिक्षा संसाधनों का अभाव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत उक्त जिलों में डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसमें अधिकांश स्कूल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में हैं और सुलभ, वहनीय, समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। यू-डाइस+ 2025-26 के अनुसार, श्रावस्ती जिले के सरकारी स्कूलों में 71 आईसीटी/कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, 462 स्मार्ट कक्षाएं, 6 भौतिकी प्रयोगशालाओं, 6 रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं और 5 जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं हैं। बलरामपुर जिले के सरकारी स्कूलों में 132 आईसीटी/कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, 357 स्मार्ट कक्षाएं, 5 भौतिकी प्रयोगशालाओं, 5 रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं और 4 जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने देश में डिजिटल और आधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहल की हैं। विशेष रूप से, आईसीटी और स्मार्ट कक्षाओं के अलावा, मंत्रालय समग्र

शिक्षा के तहत पीएम ईविद्या, दीक्षा और स्वयम जैसी डिजिटल पहलों को लागू करता है ताकि

देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के आकांक्षी जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा VI से XII तक की सरकारी स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन/अनुमोदन योजना के कार्यक्रमिक और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से पीएबी द्वारा किया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तावों को योजना के मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राष्ट्र की एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर-कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) उपलब्ध कराता है। दीक्षा में एक प्रतिभागी के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी) ने मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री जनित और योगदान की है, जिससे बहुभाषावाद को सक्षम बनाया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ई-सामग्री का ब्यौरा https://diksha.gov.in/data/ पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 836 से अधिक वर्चुअल लैब्स तक भी पहुंच है, जो उन्हें वास्तविक दुनिया की प्रयोगशाला वातावरण के सिमुलेशन में सहायता करती हैं। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पहुंच का समर्थन करता है, जिससे शिक्षार्थी सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सीखना जारी रख सकते हैं। वर्ष 2025-26 में, उत्तर प्रदेश राज्य में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग 2.24 लाख से अधिक छात्रों, 11 लाख शिक्षकों और 0.13 लाख माता-पिता द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 26.89 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता, 254 सक्रिय पाठ्यपुस्तकें हैं और 17,000 से अधिक ई-सामग्री का योगदान दिया गया है।

पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो देश भर में शिक्षा तक बहु-मोड पहुंच सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करती है। पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी संरेखित हैं और इसमें कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400

रेडियो चैनल शामिल हैं। पीएम ई-विद्या 200 डीटीएच टीवी चैनल पहल के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य को पांच समर्पित चैनल (यूपी पीएम ई-विद्या 173-177) आवंटित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और कक्षा शिक्षण-अधिगम पद्धतियों को बढ़ाने के लिए, संरचित शिक्षाशास्त्र-आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम), जिसमें शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ, कार्यपुस्तिकाएँ, गणित किट और शिक्षक डायरियाँ शामिल हैं, प्रदान की गई हैं। शिक्षाशास्त्रीय प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक आमने-सामने शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसे सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से निरंतर ऑन-साइट शैक्षणिक सहायता द्वारा पूरक किया जाता है। इसके अलावा, शिक्षकों के बीच सहकर्मी शिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह शिक्षक संकुल बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना, आदर्श स्कूल बनना और पड़ोस के अन्य स्कूलों को बेंचमार्किंग में नेतृत्व प्रदान करना है। वर्तमान में, बलरामपुर जिले में 19 पीएम श्री स्कूल कार्यरत हैं (जिसमें 1 केंद्रीय विद्यालय और 1 नवोदय विद्यालय शामिल हैं) और श्रावस्ती जिले में 13 पीएम श्री स्कूल हैं (जिसमें 1 केंद्रीय विद्यालय और 1 नवोदय विद्यालय शामिल हैं)।

****